

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राशन कार्ड में आधार सीडिंग से लाभार्थियों को मिलेगा नेशनल  
पोर्टेबिलिटी का फायदा

— शासन सचिव

जयपुर, 11 नवम्बर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने कहा कि प्रदेश में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य अभियान के तौर पर लिया जावेगा।

श्री जैन बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश के सभी अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधार सीडिंग के कार्य में उचित मूल्य दुकानदार तथा ई-मित्र संचालक मुख्य भूमिका निभायेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी स्वयं अथवा उचित मूल्य दुकानदारों की सहायता से गांव में स्थित या नजदीकी ई-मित्रों के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जानकारी देकर राशन कार्ड में आधार कार्ड सीडिंग निःशुल्क करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड सीडिंग कार्य के लिए उचित मूल्य दुकानदारों तथा ई-मित्र संचालकों को विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की प्रविष्टि के लिए 1-1 रुपये का भुगतान किया जावेगा।

शासन सचिव ने कहा कि आधार सीडिंग के बाद 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य प्रदेश से बाहर मजदूरी अथवा शिक्षा के लिए माईग्रेट करता है तो वहां पर भी उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने बताया कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना का लाभ उठाने के लिए आधार सीडिंग का कार्य करवाया जा रहा है, जो प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, शेष लाभार्थियों को आधार सीडिंग से जोड़ने के लिए 25 नवम्बर तक कार्यवाही की जायेगी।

श्री जैन ने बताया कि आधार सीडिंग कार्य की प्रतिदिन विभाग के अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जावेगी। उन्होंने बताया कि आधार सीडिंग कार्य में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा तकनीकी मदद प्रदान की जावेगी। उन्होंने सभी जिला रसद अधिकारियों को बताया गया कि प्रविष्टि से बचे हुए लाभार्थियों की सूची पूर्व में भिजवाई जा चुकी है, जिससे उनके लिए कार्य योजना बनाया जाना आसान होगा।

विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान आधार सीडिंग के संबंध में जिला रसद अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए, जिसके संबंध विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

विडियो कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, उपायुक्त प्रथम श्री अशोक कुमार साँखला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।